Ministry of Coal

CPSEs get two Coking Coal Mines; to Boost Production by 10 MT Per Annum

Posted On: 14 DEC 2019 6:49PM by PIB Delhi

The Ministry of Coal has allotted two Coking Coal mines, Rohne and Rabodih, to the Steel Central Public Sector Enterprises (CPSE's). Allocated under the Coal Mines (Special Provision) Act, 2015, these mines located in Jharkhand will add about more than 10 MT per annum and boost the coking coal production in the country. This is a significant step towards reducing the dependence of Steel Industry on imported coal.

The **'Rohne' Coal Mine** has been allotted to **National Mineral Development Corporation** Limited for Sale of Coal and will also serve the purpose of captive use of coking coal to NMDC's upcoming steel plant at Nagarnar.

The **'Robodih OCP' coal mine** has been allotted to **Rashtriya Ispat Nigam Limited** for captive use of production of Iron & Steel.

These mines will, over their lifetime, generate about Rs. 7000/- crore revenue for State Government, besides royalties and other applicable taxes. Both NMDC and RINL would set up their Washeries for washing coal.

This allotment is in addition to 5 coal mines which have been allocated to successful bidders and 6 coal mines which have allotted to PSU's. In all, the 13 mines will add more than 35 MT per annum coal to the domestic availability of coal. Apart from the royalties and applicable taxes, the mines are slated to generate about Rs.31000/- crore revenue over their lifetime for State Governments.

*****

SP

(Release ID: 1596504) Visitor Counter : 235

Read this release in: Hindi

कोयला मंत्रालय

सीपीएसई को दो कोकिंग कोयला खदानों का आवंटन; प्रति वर्ष 10 मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

प्रविष्टि तिथि: 14 DEC 2019 6:49PM by PIB Delhi

कोयला मंत्रालय ने स्टील सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) को दो कोकिंग कोयला खदानों, रोहने और रोबोडीह का आवंटन किया है। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत किए गए इस आवंटन से झारखंड में स्थित इन खदानों से प्रति वर्ष लगभग 10 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन के साथ-साथ देश में कोकिंग कोयले के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। आयातित कोयले पर स्टील उद्योग की निर्भरता को कम करने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को कोयले की बिक्री के लिए रोहने की कोयला खदान का आवंटन किया गया है और यह नगरनार में एनएमडीसी के आगामी स्टील प्लांट में कोकिंग कोयले के कैप्टिव उपयोग के उद्देश्य को भी पूर्ण करेगा।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को रोबोडीह ओसीपी कोयला खदान का आवंटन लौह और इस्पात के कैप्टिव उपयोग के लिए किया गया है।

इन खदानों के जीवन काल के दौरान, राज्य सरकार के लिए अन्य लागू करों एवं रॉयलटी के अलावा लगभग 7000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया जा सकेगा। कोयले की धुलाई के लिए एनएमडीसी और आरआईएनएल दोनों अपनी-अपनी वाशरियों की स्थापना करेंगी।

यह आबंटन उन 5 कोयला खदानों के अलावा है, जिन्हें सफल बोलीदाताओं को आवंटित किया गया है और 6 कोयला खदानों को सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को आवंटित किया गया है। कुल मिलाकर, 13 खदानें प्रति वर्ष कोयले की घरेलू उपलब्धता में 35 मीट्रिक टन से अधिक की बढ़ोतरी करेंगी। रॉयल्टी और लागू करों के अलावा, यह खदानें राज्य सरकारों के लिए अपने जीवनकाल में लगभग 31000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न करेंगी।

*****

आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसएस/एसएस/-4767

(रिलीज़ आईडी: 1596509) आगंतुक पटल : 79

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English